भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3984
उत्तर देने की तारीख 12 अगस्त, 2026

उच्च-स्तरीय सहभागिता

3984. **श्री अरविंद गणपत सावंतः**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) दिनांक 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल के परिसरों का उपयोग करने के लिए दूरसंचार विभाग और बीएसएनएल से लंबित कुल बकाया किराया राशि कितनी है और इसकी वसूली में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं;
(ख) क्या दूरसंचार विभाग पर 67,92,21,858 रुपये और बीएसएनएल पर 223,66,06,346/- रुपये का किराया बकाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) 31 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार उप-रजिस्ट्रार (22.13 करोड़ रुपये), आयकर (21.25 करोड़ रुपये) और एमएनएलयू (18.16 करोड़ रुपये) सहित अन्य सरकारी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और संस्थाओं से कुल बकाया राशि का ब्यौरा क्या है, जिससे वसूल ना किए जा सकने योग्य किराये का कुल योग 161,22,01,440.02 रुपये हो जाता है; और
(घ) विभिन्न राज्य मंत्रालयों, मंत्रालयों और केंद्रीय विभागों से उक्त बकाया राशि की वसूली के लिए तैयार की गई ठोस कार्ययोजना और उच्च-स्तरीय सहभागिता कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) पूर्ववर्ती डाक और तार विभाग को वर्ष 1985 में डाक विभाग और दूरसंचार विभाग में विभाजित किया गया था। इसके बाद, 1986 में, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)

का गठन किया गया था तथा दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार सेवाओं के नियंत्रण, प्रबंधन और प्रचालन की जिम्मेदारी, जो अब तक दूरसंचार विभाग के पास थी, एमटीएनएल को सौंपी गई थी। उक्त विभाजन और प्रचालनों को सौंपने के बाद, उक्त विभाग और एमटीएनएल ने कई परिसरों में स्थान का उपयोग करना जारी रखा जो पूर्ववर्ती अविभाजित विभाग से संबंधित थे। हालांकि, उस समय इस तरह के उपयोग की शर्तें तय नहीं की गई थीं। वर्ष 2000 में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की स्थापना के बाद दूरसंचार विभाग की शेष दूरसंचार सेवाओं से संबंधित प्रचालनों को सौंपने के बाद यह जारी रहा। परिणामस्वरूप, बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा साझा किए गए परिसरों के इस प्रकार के उपयोग के प्रतिफल को दोनों के बीच अंतिम रूप नहीं दिया गया है, और इस संबंध में दोनों में चर्चा चल रही है।

दूरसंचार विभाग ने विभाग की इकाइयों द्वारा अधिग्रहित स्थान के लिए एमटीएनएल को विभाग द्वारा देय मुआवजे/देय राशि के संबंध में सिफारिश करने के लिए विभाग और एमटीएनएल दोनों के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है।

दिनांक 31.5.2026 तक अन्य सरकारी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और संस्थानों से एमटीएनएल का कुल बकाया लगभग 155.5 करोड़ रुपये है। एमटीएनएल लंबित देय राशियों के भुगतान के लिए नियमित रूप से प्रयास करता है और इसके लिए विशेष अभियान भी चलाता है।

***